SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Considering the appeal made by the Minister and having the faith that he will be fulfil his assurance, I withdraw the Resolution.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I shall now put the Motion moved by Shri M. Thambi Durai to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 9 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI S. THAMBI DURAI: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE FINANCE (AMENDMENT) BILL, 1998

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Finance Act, 1979 and the Finance (No. 2) Act, 1996, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Taking into account a number of commitments made after the budget of 1997, including the pay commission award, the previous Government had, in order to raise additional resources, increased the special duty of customs on all imports (excluding POL and project imports) from 2% to 5% ad valorem and also raised the foreign travel tax for journeys undertaken to non-neighbouring countries from Rs. 300 to Rs. 750 per passenger. As the Parliament was not in session the legislative amendments required in section 35 of the Finance Act, 1979 and section 68 of the Finance (No. 2) Act, 1996 for implementing the above changes were effected by issue of an Ordinance, namely the Finance Act (Amendment) Ordinance, 1997 (No. 16 of 1997) dated the 16th September, 1997.

The above mentioned ordinance could not be replaced by a Bill during the winter session as the 11th Lok Sabha was dissolved. In order to enable the Government to continue to levy of Special customs duty and the foreign travel tax at the enhanced rates, another Ordinance was promulgated, namely the Finance (Second Amendment) Ordinance, 1997 (No. 24 of 1997) dated the 24th December, 1997 with the modification that the foreign travel tax was reduced from Rs. 750 to Rs. 500 per passenger, for journeys undertaken to non-neigh bouring countries with effect from the 1st January, 1998.

The Finance (Second Amendment) Ordinance, 1997 could also not be replaced by a Bill, as after the General Elections, the Parliament met only for a very short duration. In order to ensure that the Govenrment could continue to levy the special duty of costoms and the foreign travel tax at the enhanced rates as envisaged under the Finance (Second Amendment) Ordinance, 1997, another Ordinance was promulgated namely the Finance (Amendment) Ordinance, 1998 (No. 5 of 1998) dated the 21st April, 1998.

I had introduced the Finance (Amendment) Bill, 1998 to replace the Finance (Amendment) Ordinance, 1998 in the Lok Sabha on 29th May,

1998. The Honorable Speaker had referred this Bill to the Standing Committee on Finance. The Standing Committee on Finance has already examined the Finance (Amendment) Bill, 1998. The Bill has been passed by the Lok Sabha on 4th July, 1998.

I seek the indulgence of this Honorable House for replacing the Finance (Amendment) Ordinance, 1998 by the Finance (Amendment) Bill, 1998.

The question was proposed.

[The Vice-Chairman (Shri Sanatan Bisi) *In the Chair]*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Shri K. Rahman Khan. He is not present. Shri Md. Salim.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Just a minute, Sir. We have not been given this revised list of business.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): The supplementary list?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Yes. We haven't received it. *(Interruptions)*

SHRI MD. SALIM (West Bengal): It has already been circulated. I think he has missed it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Just a minute. Please take your seat.

SHRI MD. SALIM: It has already been circulated in the House. I have got an extra copy. I can give it to you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I am giving the orders for its circulation.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am not going into the technicalities. But the fact remains that we haven't got it in today morning's business papers. It migth have been circulated at the time when I wasn't here. But certainly, this is not the way we should function. Anyway, I am not going into it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Okay, Can we go ahead now? Shri Md. Salim, please.

श्री मोहम्मद सलीम : वाइस चेयरमैन सर, मंत्री महोदय ने इस मोशन को मूव करते समय अपनी बातों को रखा । सर, सरकार एक कांटीन्यूअस एन्टीरी हैं । पुरानी सरकार के समय एक आर्डिनेंस सितम्बर, 1997 में आया, फिर दिसम्बर, 1997 में आया और फिर अप्रैल, 1998 में एक आर्डिनेंस आया । तो यह एक क्लासिक केस हैं कि किस तरह से सरकार आर्डिनेंस के थ्रू गर्व्न करती हैं और किस तरह से पार्लियामेंट के और इस सदन के जो अधिकार हैं, इस देश की जनता के जो अधिकार है, उनको नज़रअंदाज़ किया जाता हैं । खासकर के नए टैक्स के प्रपोज़ल के बारे में आप एक आर्डिनेंस लाएं, रुपया कलेक्ट किया, फिर एक आर्डिनेंस आ गया और फिर तीसरी बार एक आर्डिनेंस जारी किया । हुकूमत बदली, मंत्री बदले लेकिन तौर-तरीका नहीं बदला और हालत वही हैं । यह इस समय या उस सरकसार की बात नहीं हैं । आपके दूसरे जो मंत्री थे खासकर लॉ-मिनिस्टर जो आर्डिनेंस क्लियर करते हैं, लॉ-मिनिस्टर कह गए कि यह तो पुरानी सरकार का किया हैं, हमारी सरकार का नहीं लेकिन आप यह नहीं कह सकते । विंटर सैशन में पास नहीं कर पाए, लोकसभा डिस्सॉल्व हो गई । फिर 12वीं लोकसभा कांस्टीट्यूट हुई, फिर हमने वोट-आन-एकाउंट किया, ऐसे आर्डिनेंसेज और भी थे –इनकम-टैक्स के बारे में भी था जिन्हें आपने पास करवाया । तो यह आर्डिनेंस भी पास हो जाना चाहिए था जो फारेन-ट्रैवल के लिए 300 रुपए की जगह 750 रुपए पेमेंट करने की बात थी । लेकिन यह आर्डिनेंस पास नही हुआ और मालूम नहीं कि यह किसने लगाया, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने लगाया या किसी और ब्यूरोक्रेट ने लगाया । यह लाखों-करोड़ों रुपए का मामला हैं । करोड़ रुपए आप कलेक्ट कर रहे हैं । कांस्टीट्यूशन के मुताबिक अगर एक रुपया भी आप पार्लियामेंट का ओपीनियन लेना पड़ता हैं । इस तरह से यह क्लासिक उदाहरण हैं कि आप किस तरह से पार्लियामेंट को रबर-स्टैप बनाते हैं । यह रिट्रोस्पैक्टिव

इफेक्ट हैं । सितंबर से हम इतने महीने पार करके चले आए, कलेक्ट आप कर चुके हैं, आपको मालूम हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को मालूम हैं, डैक्स-आफिसर को मालूम हैं कि सदन इसको पासर कर देगा । अन्यथा जितना रुपया आपने कलेक्ट किया, पिछले सितंबर महीने से जितने पैसेंजर्स थे, सबको वापस करना पड़ेगा । यह मुश्किल काम हैं ।

यह ताकत इसलिए दी गई हैं ताकि मजबूरी में इसका उपयोग किया जाए । यह केवल आपकी सरकार का सवाल नहीं हैं । जो भी सरकार आए, उसे इस बारे में भी में ध्यान रखना चाहिए । जो ब्यूरोक्रेट्स वहां बैठे हुए हैं, आज जो ओवर-ब्यूरोक्रेटाइजेशन हुआ हैं, जिस तरह से ऐक्जीक्यूटिव को पावर्स दी गई हैं उससे लेजिस्लेचर्स को ऐक्जीक्यूटिव रबर-स्टैप की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं जब कि उल्टा होना चाहिए था यानी ऐक्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर्स का रबर-स्टैप बनना चाहिए था । इस केसे में ब्यूरोक्रेसी ने जो फैसला लिया, उसे आप अब यहां लेकर लेजिस्लेचर की स्टैप लगवा रहे हैं । यही मामला कस्टम के बारे में भी हैं ।

महोदय, अब मैं विषय पर आना चाहता हूं । कस्टम ड्यूटी के बारे में अपने यह कहा कि कोई समय सीमा बिल में नहीं हैं लेकिन जब यह लागू हुआ था 2 परसेंट से 5 परसेंट, जो पहले आर्डिनेंस में आया था, फिर सेकेंड आर्डिनेंस और थर्ड आर्डिनेंस में भी रिपीट किया गया तो मंत्री महोदय ने सदन में आवश्वासन दिया था कि 1999 के मार्च तक यह लागू होगा कस्टम-ड्यूटी 2 से 5 परसेंट करने का । लेकिन फारेन ट्रैवल टैक्स के बारे में कोई आश्वासन नहीं हैं । जो आप आलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे देश की जनता जब बाहर जाएगी, उस पर जो टैक्स उसे देना पड़ेगा, उसके बारे में कोई आश्वासन नहीं हैं कि यह अचानक आना पड़ा । हमारे खर्चे ज्यादा हो गए, हमें पे-कमीशन की रिकमंडेशस माननी पड़ी और उसके लिए यह आर्डिनेंस लाना पड़ा । इज़ी वे क्या है —टैक्स बढ़ा दो । पिछली सरकार ने मान लिया, टैक्स बढ़ा दिया लेकिन एक बार जब बढ़ जाता हैं तो फिर घटता नहीं हैं । पिछली सरकार ने इसे 300 रुपए से 750 रुपए कर दिया था । आप इसे 750 रुपए से 500 रुपए ले आए । इसका मतलब हैं कि कुछ प्रबंध हुआ हैं । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह रेट बढ़ाकर आपने कितना फंड जुटाया इसके जरिए और कितना जुटाना चाहते हैं ।

महोदय, आर्डिनेंस इसलिए लाते हैं जब कोई अनप्रिसिडेंटेड सिचुएशन आ जाए, साईक्लोन आ जाए, फ्लड आ जाए, या आज की स्थिति में युद्ध वगैरह हो जाए तो हम आर्डिनेंस लाने की बात समझ सकते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पे-कमीशन तो ऐक्जीक्यूटिव बनाती हैं । पे-कमीशन जब बना तो उसकी जो राय हैं, उसका जो डिसीजन हैं, उसे लागू करने के लिए करने के लिए ही आप बनाते हैं । अगर उसकी रिकमंडेशंस को आप लागू करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रोविजन सोचना चाहिए । आपकी सरकार कह रही हैं कि यह प्रो-ऐक्टिव हैं । कोई भी सरकार हो, उसके प्रो-ऐक्टिव होना चाहिए लेकिन जब आप पे-कमीशन बनाते हैं तो खुद उसके लिए टाईम देते हैं कि एक साल, दो साल या पांच साल में ये राय करके ले आएंगे अपनी रिपोर्ट आपको संसाधन जुटाने का बंदोबस्त रखना चाहिए लेकिन आपने नहीं रखा हैं । आपसे मतलब पिछली गवर्नमेंट ने नहीं रखा हैं । मैं इस सवाल को पार्टी के आधार पर या सरकार के आधार पर नहीं बांटना चाहता । एक्जीक्यूटिव के ऊपर यह होता हैं कि वह इसको लागू करें । जब यह लागू करते हैं तो उसके लिए साधन क्यों नहीं सोचकर रखते हैं । या तो हम जो कमीशन या कमेटियां बनाते हैं धोखाधड़ी के लिए बनाते हैं कि चलो वह बन गया, उसके लिए रुपया आएगा देखा जाएगा । मैं इसलिए कह रह हूं कि भविष्य के लिए गवर्नमेंट जो कहती है कि हम प्रो-एक्टिव हैं, आप जब कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे तो आपको प्रो-एक्टिव होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसका साधन कि कहां से जुटाते हैं । दूसरी बात हैं कि इस बार बजट आ गया । बजट आने से आपने साधन जुटा लिया । पे-कमीशन के बारे में पता नहीं था लेकिन बाद में इतने हजार-करोड़ रुपया खर्च होगा उसका आंकड़ा बैठ गया । आप लागू कर रहे हैं । अभी जजेज बिल के बारे में हमने एक्ट पास किया हैं । अब इसकी बढ़ोत्तरी की क्या जरूरत हैं, आपको व्याख्या देनी पड़ेगी । सितम्बर, से दिसम्बर या दिसम्बर से अप्रैल या अप्रैल से इस बजट तक अगर आप 300 से 500 करते हैं या 750 करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो खर्च आपके साथ नहीं था वह साधन जुटाने के लिए आपने किया । लेकिन इस बजट के बाद जब आप बोलते हैं कि हम पे-कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए वह साधन जुटा लिए हैं तो अब जो 300 से 500 कर रहे हैं वह चलता रहेगा उसके कोई अपर लिमिट भी नहीं हैं । तो वह साधन आप किसके लिए जुटा रहे हैं वह रुपया कहां जाएगा ? जब आप जनता के ऊपर टैक्स डाल रहे हैं और इस

आर्डिनेस के समय में जो व्याख्या आपने नहीं दो तो इस बिल को पास करते समय आपको नेशन को यह व्याख्या देनी पड़ेगी कि यह जो 300 से 500 कर रहे हैं इसके पीछे कारण क्या हैं और यह रुपया कहां जाएगा। इसी के साथ यह भी मामला जुड़ा हुआ हैं कि फारेन ट्रेवल टैक्स जब हम कलक्ट करते हैं तो बनिखत हम कोई सर्विस देते हैं। आपको मालूम होगा पिछले कई वर्षो से यह चल रहा हैं, तीन-चार गवर्नमेंट इस बीच में बदल गई हैं। फारेन ट्रेवल टैक्स जो एयरपोर्ट में कलेक्ट किया जाता हैं, एयरपोर्ट का जो हमारा इंफ्रास्ट्रकर हैं उसमें काफी दिक्कत हैं, आप क्यों प्राइवेट सैक्टर को बुला रहे हैं, इधर बुला रहे हैं, उधर बुला रहे हैं वह हो नहीं रहा हैं। इसमें हजारों, करोड़ो लागत की जरूरत हैं। पैसेंजर्स एमिनिटीज बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्टकर को बढ़ाने के लिए जो रुपया आप कलेक्ट कर रहे हैं वह आप रिटर्न कर रहे हैं या नहीं जो फारेन ट्रेवल के लिए जाए या डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए तथा जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रकर हैं उसमें खर्च करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ऐसी रिकमंडेशंस गई थी, आपके सैक्रेट्रीज की कमेटी बनी थी केबिनेट नोट बना था, केबिनेट तक पहुंचे थे। पिछले तीन सरकारों के जमाने की बता रहा हूं। फारेन ट्रेवल टैक्स का एक शेयर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री चाहती हैं ताकि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रकर को बढ़ाने के लिए मदद मिले। जो टूरिस्ट हैं, जो पैसेंजर हैं उनको और भी किस तरह से सहायता दी जा सके। जो रुपया आप कलक्ट कर रहे हैं उनको फिर आप किस हद तक कहां तक रिटर्न करेंगे और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री रुपए अदा करेगी 500 रुपया करके प्रति पैसेंजर, तो उसके शेयर के बारे में आपने कुछ निर्णय लिया हैं या नहीं लिया हैं कि कितना वह एयरपोर्ट पर वापिस आ जाएगा या पैसेंजर्स के बारे में वापिस आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रकर डवलपमेंट के लिए वापिस आ जाएगा।

जहां तक कस्टम ड्यूटी का मामला हैं उसमें समय निर्धारित हैं मार्च, 99 तक कलक्ट होगा। मैंने देखा हैं कि आपने उस सदन में भी शनिवार को रैफर किया हैं। आप तो स्वदेशी सरकार हैं, आप तो चिदम्बरम् नहीं हैं। चिदम्बरम् जी यह कहते थे कि जब दो परसेंट से पांच परसेंट कर दिया कस्टम ड्यूटी इंक्रीज करने के लिए उसका एक टाईम रख दिया था कि मार्च, 99 तक होगा। आपका जो यह स्वदेशी स्टेम्प वाला बजट हैं और स्वदेशी जरसी पहने हुए जो मंत्री हैं उनसे तो मैं इतनी उम्मीद करूंगा कि वह तमाम चीजें जिनको हमारे यहां डामेरिस्टक सैक्टर में कम्पटीशन करना पड़ता हैं जिसके साथ हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको कम्पटीशन में आना पड़ता हैं तो उसके ऊपर जो आपने दो परसेंट से 5 परसेंट बढ़ाए हैं, यह आसान काम हैं, पैसेजर्स विदेश जा रहे हैं आप उनसे कलक्ट करते रहेंगे जिसका कोई टाईम लिमिट नहीं हैं और जो विदेश से सामान आएगा उसका आपने टाईम लिमिट कर दिया हैं कि वह मार्च, 99 तक रहेगा। आप देशी जनता से साधन जुटा रहे हैं। अगर विदेशी कम्पनियों के पास से भी साधन जुटाएं तो अच्छा रहेगा। मेरी यह रिक्वेस्ट रही हैं यह उम्मीद रही कि रिफ्लेक्शन हैं वह आपके कारनामें में भी होना चाहिए। धन्यवाद।

†**شری محمد سلیم" پشچمی بنگال":** وائس چیئر مین۔ سر، منتری مہودے نے اس موشن کو موو کرتے وقت اپنی باتوں کو رکھا۔ سر، سرکار ایک کنٹی نیوس اینٹی ہے۔ پرانی سرکار کے وقت ایک آرڈیننس ستمبر، ۱۹۹۷ میں آیا، پھر دسمبر ۱۹۹۷ میں آیا اور پھر اپریل ۱۹۹۸ میں ایک آرڈننس آیا۔ تو یہ ایک کلاسک کیس ہے کہ کس طرح سے سرکار آرڈننس کے تھروگورن کرتی ہے اور کس طرح سے پارلیمنٹ کے اور اس سدن کے جوادھیکار ہیں، اس دیش کی جنتا کے جو ادھیکار ہیں، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سرکار کے نئے ٹیکس کے پروپوزل کے بارے میں آپ ایک آرڈننس لائے، روپیہ کلیکٹ کیا، پھر ایک آرڈننس آ گیا، اور پھر تیسری بار ایک آرڈننس جاری کیا۔ حکومت بدلی۔ منتری بدلے لیکن طور

†[]Transilteration in Arabic Script

اسٹیمپ بنا تے ہیں۔ یہ رٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے۔ ستمبر سے ہم اتنے مہینے پار کر کے چلے گئے، کلیکٹ آپ کر چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے، فائننس منسٹری کو معلوم ہے، ڈیسک آفیسر کو معلوم ہے کہ سدن اس کو پاس کر دیگا۔ انیتھا جتنا روپیہ آپ نے کلیکٹ کیا، پچھلے ستمبر مہینے سے جتنے پینجر تھے سب کو واپس کرنا پڑیگا۔ یہ مشکل کام ہے۔

یہ طاقت اس لئے دی گئی ہے تاکہ مجبوری میں اس کا اپیوگ کیا جائے۔ یہ کیول آپکی سرکار کا سوال نہیں ہے۔ جو بھی سرکار آئے، اسے اس بارے میں دھیان رکھنا چاہئے۔ جو بیورو کریٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو اوور بیوروکریٹائزیشن ہوا ہے، جس طرح سے ایکزیکیٹیو کو پاورس دی گئی ہیں اس سے، لجس لچر، کا ربر اسٹیمپ بننا چاہئے تھا۔ اس کیس میں بیوروکریسی نے جو فیصلہ کیا، اسے آپ اب یہاں لاکر 'لجس لچر' کی اسٹیمپ لگوا رہے ہیں۔ یہی معاملہ کسٹم ڈیوٹی کے بارے میں بھی ہے۔

مہودے اب میں وشے پر آنا چاہتا ہوں۔ کسپم ڈیوٹی کے بارے میں آپ نے کہا کہ کوئی سمے سیابل میں نہیں طریقہ نہیں بدلا اور حالت وہی ہے۔ یہ اس سرکار یا اس سرکار کی بات نہیں ہے۔ آپ کے دوسرے جو منتری تھے خاص کر لاء منسٹر، جو آرڈننس کلیئر کرتے ہیں، لا منسٹر کہہ گئے کہ یہ تو پرانی سرکار کا کیا ہے ہماری سرکار کا نہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ونٹر سیشن میں پاس نہیں کر پائے، لوک سبھا ڈزالو ہوگئی۔ پھر ۱۲ ویں لوک سبھا کانسئی ٹیوٹ ہوئی۔ پھر ہم نے ووٹ آن اکاؤنٹ کیا، ایسے آرڈننسز اور بھی تھے۔ انکم ٹیکس کے بارے میں بھی تھا، جنہیں آپنے پاس کرایا۔ تو یہ آرڈننس بھی پاس ہو جانا چاہئے تھا جو فارا ٹریول کیلئے ۳۰۰ روپے کی جگہ ۷۵۰ روپے پیمنٹ کرنے کی بات تھی۔لیکن یہ آرڈننس پاس نہیں ہوا اور معلوم نہیں کہ یہ کس نے لگایا، جوائنٹ سکریٹری نے لگایا یا کسی اور بیوروکریٹ نے لگایا۔ یہ لاکھوں، کروڑوں روپے کا معاملہ ہے۔ کروڑوں روپے آپ کلیکٹ کر رہے ہیں۔ کانسٹی ٹیوشن کے مطابق اگر آپ ایک روپیہ بھی آپ خرچ کرتے ہیں یا کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے پارلیمنٹ کا اوپینین لینا پڑتا ہے۔ اس طرح سے یہ کلاسک ادھارن ہے کہ آپ کس طرح سے پارلیمنٹ کو ربر

چاہتا ہوں کہ یہ ریٹ بڑھا کر آپنے کتنا فنڈ جٹا یا، اسکے ذریعہ اور کتنا جٹانا چاہتے ہیں؟

مہودے آرڈننس اس لئے لاتے ہیں جب کوئی 'ان پریسیڈنٹیڈ سچوایشن ' آجائے، سائکلون آجائے فلڈ آجائے، یا آج کی استتھی میں یدھ وغیرہ ہو جائے تو ہم آرڈننس لانے کی بات سمجھ سکتے ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ پے کمیشن تو ایکزیکیٹیو بناتی ہے۔ پے کمیشن کو پار لیمنٹ نے اپائینٹ کیا ہے۔ آپ کا پے کمیشن جب بنا تو آپ کی جو رائے ہے، اسکا جو ڈسیزن ہے،ا سے لاگو کرنے کے لئے ہی آپ بناتے ہیں۔ اگر اس کی ریکمنڈیشن کو آپ لاگو کرنا چاہتے ہیں تو آپکو اسکے لئے پرویزن سوچنا ہوگا۔ آپ کی سرکار کہہ رہی ہے کہ وہ پرو۔ ایکٹیو' ہے۔ کوئی بھی سرکار ہو، اسکو پڑو۔ ایکٹیو، ہونا چاہئے، لیکن جب آپ پے کمیشن بناتے ہیں تو خو اسکے لئے ٹائم دیتے ہیں کہ ایک سال ، یا پانچ سال میں یہ رائے کر کے آیئنگے اپنی رپورٹ آپ کو اس کا سنسادھن جٹانے کا بندوبست رکھنا چاہئے لیکن آپنے نہیں رکھا ہے۔ آپ سے مطلب پچھلی گورنمنٹ ہے لیکن جب یہ لاگو ہوا تھا دو پرسینٹ سے پانچ پرسینٹ، جو پہلے آرڈننس میں آیا تھا، پھر سیکنڈ آرڈننس اور تھرڈ آرڈننس میں بھی رپیٹ کیا گیا تو منتری کیا گیا تو منتری مہودے نے سدن میں آشواسن دیا تھا کہ ۱۹۹۹ کے چرچ تک یہ لاگو ہوگا کسٹم ڈیوٹی ۲ سے ۵ پرسینٹ کرنے کا۔ لیکن فارن ٹریول ٹیکس کے بارے میں کوئی آشواسن نہیں ہے۔ جو آپ آل ریڈی کلیکٹ کر رہے ہیں، ہمارے دیش کی جنتا جب باہر جائے گی،اس پر جو ٹیکس ا سے دینا پڑیگا، اس کے بارے میں کوئی آشواسن نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گا۔ اس کو لگانے کے پیچھے آپ کا لاجک یہ ہے کہ یہ اچانک آن پڑا۔ ہمارے خرچے زیادہ ہو گئے۔ ہمیں پے کمیشن کی رکمنڈیشن ماننی پڑیں۔ اور اس کے لئے یہ آڈننس لانا پڑا۔ 'ایزی وے'کیا ہے... ٹیکس بڑھادو۔ پچھلی سرکار نے مان لیا، ٹیکس بڑھا دیا لیکن ایک بار جب بڑھ جاتا ہے تو پھر گھٹتا نہیں ہے۔ پچھلی سرکار نے ا سے ۳۰۰ روپئے سے ۷۵۰ روپے کر دیا تھا۔ آپ ا سے ۷۵۰ روپے سے ۵۵۰ روپے لے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ پر بندھ ہوا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا

کہ جو خرچ آپ کے ساتھ نہیں تھا وہ سادھن جٹانے کے لئے آپ نے کیا۔ لیکن اس بجٹ کے بعد جب آپ بولتے ہیں کہ ہم پے کمیشن کی رپورٹ لاگو کرنے کے لئے وہ سادھن جٹالئے ہیں تو اب جو ۳۰۰ سے ۵۰۰ کر رہے ہیں وہ چلتا رہیگا اسکے کوئی اوپر لیمٹ بھی نہیں ہے۔ تو وہ سادھن آپ کس کے لئے جٹا رہے ہیں، وہ روپیہ کہاں جایئگا؟ جب آپ جنتا کے اوپر ٹیکس ڈال رہے ہیں اور اس آرڈنس کے وقت میں جو ویاکھیا آپ نے نہیں دی تو اس بل کو پاس کرتے وقت نیشن کو یہ ویاکھیا دینی پڑیگی کہ یہ جو ۳۰۰ سے ۵۰۰ کر رہے ہیں اسکے پیچھے کارن کیا ہے اور یہ روپیہ کہاں جائیگا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی معاملہ جڑا ہوا ہے کہ فارین ٹریول ٹیکس جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو یہ نسبت کوئی سروس دیتے ہیں۔ آپ کو معالوم ہوگا پچھلے کئی ورشوں سے یہ چل رہا ہے، تین چار گورنمنٹ اس پیچ میں بدل گئی ہے۔ فارن ٹریول ٹیکس جو ائر پورٹ میں کلیکٹ کیا جاتا ہے، ایئر پورٹ کا جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس میں کافی دقت ہے، آپ کیول پرائیویٹ سیکٹر کو بلا رہے نے نہیں رکھا ہے۔ میں اس سوال کو پارٹی کے آدھار پر یا سرکار کے آدھار پر نہیں بانٹنا چاہتا۔ ایکزیکٹیو کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکو لاگو کریں۔ جب وہ لاگو کرتے ہیں تو اس کے لئے سادھن کیوں نہیں سوچ کر رکھتے ہیں۔ یا تو ہم کمیشن یا کمیٹیاں بناتے ہیں دھوکہ دھڑی کے لئے بناتے ہیں کہ چلو وہ بن گیا، اس کے لئے روپیہ آئے گا دیکھا جائیگا۔ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بھوشے کے لئے گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ ہم 'پرو۔ایکٹیو' ہیں، آپ جب کچھ ایسے اسٹیپس لینگے تو آپ کو 'پرو۔ایکٹیو' ہونا پڑیگا، سوچنا پڑیگا اس کا سادھن کہاں سے جٹاتے ہیں۔دوسری بات ہے کہ اس بار بجٹ آگیا۔ بجٹ آنے سے آپنے سادھن جٹا لیا۔ پے کمیشن کے بارے میں پتہ نہیں تھا لیکن بعد میں اتنے ہزار کروڑ روپیہ خرچ ہوگا اسکا آنکڑا بیٹھ گیا۔آپ لاگو کر رہے ہیں۔ ابھی ججیزیل کے بارے میں ہم نے ایکٹ پاس کیا ہے۔ اب اس کی بڑھوتری کی کیا ضرورت ہے، آپکو ویوستھا دینی پڑیگی۔ ستمبر سے دسمبر یا دسمبر سے اپریل یا اپریل سے اس بجٹ تک اگر آپ ۳۰۰ سے ۵۰۰ کرتے ہیں یا ۷۵۰ کرتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں

ڈیولپمنٹ کے لئے واپس آجائیگا۔ جہاں تک کسٹم ڈیوٹی کا معاملہ ہے اس میں وقت مقرر ہے مارچ ۱۹۹۹ تک کلیکٹ ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس سدن میں بھی سنیوار کو ریفر کیا ہے۔ آپ تو سودیشی سرکار ہیں، آپ تو چدمبر نہیں ہیں۔ چدمبر جی یہ کہتے تھے کہ جب دو پرسینٹ سے پانچ پرسینٹ کر دیا کسٹم ڈیوٹی انکریز کرنے کے لئے اسکا ایک ٹائم رکھ دیا تھا کہ مارچ ۱۹۹۹ تک ہوگا آپکا جو یہ سودیشی اسٹیمپ والا بجٹ ہے اور سودیشی جرسی پہنے ہوئے جو منتری ہیں ان سے تو میں اتنی امید کرونگا کہ وہ تمام چیزیں جن کو ہمارے یہاں ڈومیسٹک سیکٹر میں کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے جس کے ساتھ ہمارے جو پروڈکٹ ہیں ان کو کمپیٹیشن میں آنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر جو آپ نے دوپرسینٹ سے پانچ پرسینٹ بڑھائے ہیں، یہ آسان کام ہے، پیسنجرس ودیش جا رہے ہیں آپ ان سے کلیکٹ کرتے رہیں گے جس کا کوئی ٹائم لمیٹ نہیں ہےاور جو ودیش سے سامان آئیگا اسکا آپ نے ٹائم لمیٹ کر دیا ہےکہ وہ مارچ ۱۹۹۹ تک رہیگا۔ آپ ودیشی جنتا سے سادھن جٹا رہے ہیں۔ اگر ودیشی کمپنیوں کے پاس سے ہیں، ادھر بلا رہے ہیں، ادھر بلا رہے ہیں، وہ ہو نہیں رہا ہے۔ اس میں ہزاروں، کروڑوں لاگت کی ضرورت ہے، پیسنجر انیمیٹیز بڑھانے کے لئے اور انفراسٹرکچر کو بڑھانے کے لئے جو روپیہ آپ کلیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ ریٹرن کر رہے ہیں یا نہیں۔جو فارین ٹریول کے لئے جائے یا ڈو میسٹک ٹریول کے لئے تتھا جو ائیر پورٹ انفراسٹرکچر ہے اس میں خرچ کرنے کے لئے فائنس منسٹری کے پاس ایسی رکمنڈیشنس گئی تھی، آپ کے سیکریٹریز کی کمیٹی بنی تھی، کیبینیٹ نوٹ بنا تھا، کیبینیٹ تک پہلے تھے۔پچھلی تین سرکاروں کے زمانے کی بتا رہا ہوں۔ فارین ٹریول ٹیکس کا ایک شیئر سول ایوی ایشن منسٹری چاہتی ہے تاکہ ایئر پورٹ انفراسٹرکچر کو بڑھانے کے لئے مدد ملے۔ جو ٹورسٹ ہیں، جو پیسنجر ہیں ان کو اور بھی کسی طرح سے مدد دی جا سکے۔ جو روپیہ آپ کلیکٹ کر رہے ہیں ان کو پھر آپ کس حد تک کہاں تک ریٹرن کرینگے اور جو فائنس منسٹری روپے ادا کریگی ۵۰۰ روپیہ کرکے فی پسنجر، تو اس کے شیئر کے بارے میں آپ نے فیصلہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے کہ کتنا وہ ایئر پورٹ پر واپس آ جائیگا یا پسنجر کے بارے میں واپس آجائیگا، انفراسٹرکچر

بھی سادھن جٹائیں تو اچھا رہیگا۔ میری یہ ریلویسٹ رہی

اور یہ امید رہی کہ آپ کی جو نیتی ہے یا جو بھاشن ہے اس

کا جو ریفلیکشن ہے وہ آپ کے کارنامے میں بھی ہونا

چاہئے۔ دھنیواد۔

5.00 P.M.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I request that my esteemed colleague may look into another aspect. Sir, the point is there has been additional taxation to mop up the resources.... *(Interruptions)*.... It was because there was a decision by the earlier Government to increase the pay-scales of the Government employees. That is quite understandable. Sir, my point is as to why .it was necessary to substitute the earlier Ordinance by another Ordinance and as to why it could not be made a part of the Budget proposals. Sir, it has always been said in the House that the way in which we are taking recourse to Ordinance is bad for the legislature. Sir, it is a question of increasing tax on foreign travel and duty on imported goods. I would like to know why it could not find place in the Budget itself. Why has an Ordinance been promulgated for this purpose when the Budget proposals themselves had their own effects? Why did the Government take recourse to promulgation of another Ordinance? Sir, this is important because this peaks of the casual character in which the finance of the country is being managed. The hon. Finance Minister will bear with me the way in which the increase in petrol prices was handled and the way the hesitant Government had to consider and reconsider—that is good for the country and not bad—the question of taxation of Urea. Sir, my point is that the finance of the country is not well-managed, is not well thought of and is not well-planned. It is just a casual way in which the bureacracy is functioning and the hon. Finance Minister always comes to the House to get something passed that was done by the earlier Government. Therefore, my point is that instead of putting these proposals in the Budget why did you issue the second or the third Ordinance? If you are going to tax foreign travel, it has its meaning. A large number of skilled and unskilled workers are going out of the country in search of jobs. I agree that those who are going out of the country and are able to pay, they should pay. I do not quarrel on that. But, the point is there is luxury foreign travel. Will you treat these two types of travels in the same way? There should be a provision in this regard. If people go out of the country in quest of job, should they be taxed in the same way in which our Foreign Minister would go to attend a conference in London? Should they be taxed in the same way in which the industrialists are taxed when they go to some other country to spend their summer because Delhi is too hot? Should they all be taxed in the same way? I would request my hon. friend to kindly take these points into consideration while replying to this debate.

SHRI R.K. KUMAR (Tamil Nadu): Sir, I support this Bill. .... *(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: This is your baby.... *(Interruptions)*....

SHRI R.K. KUMAR: This is not my bady. This is Government's baby. Sir, I am in the Treasury Benches. Normally, rule by Ordinance is opposed by all including my friends on the Treasury benches. On this occasion, I respectfully recall late Satish Agarwalji who always used to oppose the Ordinances. He used to give a motion for disapproval of the Ordinances whenever they were promulgated. Sir, rule by Ordinances is not liked by anybody and more so any tax proposals through an Ordinance. But, then this is the legacy of the previous Government and without sounding to answer on behalf of the Finance Minister, I would like to say perhaps this is the last

Ordinance preomulgatcd on the 21st April, 1998. This is probably because on 21st April 98, the date when the Budget would be presented was not finalised. When I was explaining this to my learned friend Shri Gurudas Das Gupta He said, "You could have included this in the Finance Bill, 1998 as a part of the Budget retrospectively." But, then any retrospective tax proposal is also opposed. Sir, this is the past legacy and in future, no doubt, this Government will take care not to rule by Ordinance particularly in respect of tax proposaals.

As regards Foreign Travel Tax, it is a retrograde thing to demand any reduction of tax or levy or fee which is against the progress. So, what one should ask for is, what service I get for this fee. The hon. Finance Minister cannot give an assurance as to what kind of service we will get in our airports. At least, he should impress upon his colleague, the hon. Minister of Civil Aviation, that as soon as this Foreign Travel Tax comes into the statute books, there should be efforts to improve the services at airports. I fully suport Mr. Salim's views. Sir, in foreign countries it is called "Passenger Amenities Fee." We are mis-naming it here as "Foreign Travel Tax." So, passenger amenities at the airports should be improved when we collect so much money from outgoing passengers, I am sure, the hon. Finance Minister will impress upon his colleague i.e., the hon. Minister of Civil Aviation. With these words, I fully support the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Dr. D. Masthan. He is not there. Mr. Viduthalai Virumbi. He is also not there.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I am grateful to the hon. Members for participating in a brief discussion on this Bill. I am also very greatfull to them for having made some very, very important points in regardc to the functioning of not only this House but the entire parliamentary system that prevails in this country. I have no hesitation in saying on behalf of the Government which I represent in this House that we are not in favour of any rule or governance through Ordinances. This is not our policy. Unless the situation is very exceptional, it will not be the policy of the Government to bring in legislations through Ordinances. In this particular case, as you are aware and the House is also aware, exceptional conditions prevailed and exceptional circumstances prevailed in the political situation of this country for the last many months.

A point has been made by my friend, Mr. Salim, that the Fifth Pay Commission's Recommendations could have been anticipated. True. I do not have to stand here and defend what the previous Government did but becasue the governance is a continuous process, 1 have to say on behalf of those whom you were supporting. The Pay Commission's Recommendations were anticipated. There was a provision also, but what was not anticipated was the final award of the Government which increased the burden on the Government by a whopping sum of something like Rs. 7,000 crores. The then Finance Minister who obviously felt that this would completely throw the entire Budgetary calculations out of gear, not only came out with this Ordinance raising Foreign Travel Tax from Rs. 300 to Rs. 750 but also impose a special customs duty in his Budget of 1996-97. He had imposed a 2% customs duty which I raised to 5% through this Ordinance. Now, the point is, whether that Government should have taken recourse to an Ordinance to levy tax. I agree. Normally, no legislation should be implemented or should be enforced through an Ordinance, much less a taxation legislation. But, an exceptional situation had arisen and therefore, the then Government decided this. I am not here to defend the.bureaucracy's wrong doing. It will also be unnecessary on our part to condemn the bureaucracy for something for which they are not guilty.

We know how the Government functions. When a Minister wants to bring an Ordinance, he has to take a paper to the Cabinet and then the Cabinet takes a collective decision to promulgate an Ordinance and make a recommendation to the President. So, it is not that the bureaucracy manipulated the whole thing and then the Government of the day was so inept and so weak that whatever the bureaucracy suggested they went ahead and recommended to the President. I would take it that the Government of the day applied its mind and then made this recommendation to the President, and then the President in his wisdom permitted the promulgation of this Ordinance.

Then, Mr. Salim is quite right in saying that there has been a steep increase as far as the Foreign Travel Tax is concerned. In fact, you will recall that initially it was increased to Rs. 750.00 from Rs. 300.00. It was brought down in the second Ordinance to Rs. 500.00 only when representations were received and it was pointed out to the then Government that it was a steep increase. Now, I am being blamed for various things in this Budget and fun is made of the fact that I have rolled this, I have rolled that. Governments do it and this roll back from Rs. 750.00 to Rs. 5.00 is another example of rolling back. then, subsequently we had a discussion on the finance Bill. I will not point out to this House as to how many roll backs had been there in the past. But, the point I am making is that, no doubt, this was a steep increase and the Government in its wisdom decided to bring it down. Then, Mr. Salim wanted to know as to how much money we are collecting. The estimate is that we will be collecting something like Rs. 290.00 crores in the full year, 1998-99 as a result of this increase from Rs. 300.00 to Rs. 500.00. Sir, the hon. Member also made a point as to what we are doing to increase or raise the level of amenities for the passegcrs. That is a question to which my colleague in the Civil Aviation Ministry is applying his mind. But, we are aware that whenever a tax is levied it goes into the common kitty and from that common kitty money goes out to various departments. There is nothing earmarked unless it is a cess. This particular case is a tax, Foreign Travel Tax, as it is called, and, therefore, it is not earmarked particularly for the Ministry of Civil Aviation. The question of improving amenities for passengers is something which is engaging the attention of the Government, and as I have said, we have discussed this with our colleague. I am confident that at a proper time he will come out with an announcement in this regard.

Sir, Mr. Salim also talked about the lapsing of these duties on 31 March, 1999. It is true that when my predecessor in office had imposed this special Customs Duty of 2 per cent in the 1996, Budget, there itself he had said that this duty which he had imposed for holding infrastructure of this country, will lapse on 31st March, 1999 and that was not amended when it was raised from 2 per cent to 5 per cent. The House is aware when I was replying to the debate on this Bill in the other House I had said that the present Government is committed to allow this extra levy to lapse on 31 March, 1999.

I will now go to the point which my dear friend, hon. Shri Gurudas Das Gupta, had raised, why we did not provide for it in the Budget. Mr. Kumar, who was in the Finance Ministry until the other day, very rightly pointed out that on 21st April when we had promulgated it for the third time, not very happily, we did not know when the Budget would come and in the Budget we could not have gone in for a restrospective legislation because those who would have gone abroad would have travelled abroad and we could not have gone and caught hold of them wherever they would have gone and said, "Now you pay Rs. 500/- instead of Rs.-300/-." It would have been a very clumsy legislation if we had applied any-

thing retrospectively. So, it was not possible to wait for the budget. These were two separate streams of legislative action. One was the Finance Amendment Bill which was following its own course and the other was the Finance Amendment Bill which I have now presented before parliament in terms of the Budget. That is why these two could not be combined in the Budget. Now, I would like to say that I deny, with all the emphasis at my command, the charge that we are treating the finances of this country in a casual manner. We are treating it with all the seriousness that it deserves. One example here and there could not be sighted as any trend that we might be following in this regard. The point that he has made is about making a distinction between different types of people who are going abroad. Mr. Gurudas Das Gupta Saheb, I treat the rich people in one category and the poor people in another category. There is a point, there is a suggestion which I am taking note of, but I am not sure whether this will stand legal scrutiny and whether we can make a distinction which cannot be sustained in law. But, by reducing the tax from Rs. 750 to Rs. 500/ — now the increase is only Rs. 200/- — the burden has been considerably reduced and I am quite confident that those who are going abroad will be able to pay this. For the neighbouring countries, as you know, the whole thing is different. Now, for the job seekers, as I said, it is a point which I have taken note of and we will see whether it is legally tenable or not. Sir, as I said and various hon. Members have also said, the Government is a continuous business, We often stand before the two Houses of parliament and have to defend what previous Governments have done. This is the manner in which our democracy functions. It has fallen to my part to pilot this Ordinance which was promulgated by the previous government. For the next few months of the current financial year, we will carry on with it and when we consider the Budget for the year 1999-2000, at that time we will clean up the Act. We will take the country in the direction in which we want to take it then. For the time being, Sir, I plead with the House to pass this Amcndent Ordinance and convert it into an Act of parliament. Thank you, very much.

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Now I will put the motion.

The question is :

"That the Bill further to amend the Finance Act, 1979 and the Finance (No. 2) Act, 1996, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI YASHWANT SINHA: I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE LOTTERIES (REGULATION) ORDINANCE, 1998.

II THE LOTTERIES (REGULATION) BILL, 1998.

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I move the Following Resolution:

"That this House disapproves of the Lotteries (Regulation) Ordinance, 1998 (No. 6 of 1998) promulgated by the President on the 23rd April, 1998."

Sir, the Government of India, sometime before, had appointed a Committee to conduct a study and make proposals for enacting a legislation regulating the lottery business. While that Committee